मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- कठुआ का हिंदू-मुस्लिम सच; कीमत देश को अदा करनी होगी! 3
- उच्च शिक्षा - आकांक्षा और संभावनाओं का अर्थशास्त्र 4
- किधर जा रहे हो,कॉमरेड? 5
- भैया ये मार्क्सवाद क्या है ? 5
- अब कृष्णा कॉलोनी की झुग्गियां तोड़ दीं! पहले आवास समस्या पैदा करती है, फ़िर झुग्गियां उजाड़ती है सरकार 8

वर्ष 31 अंक -20 फ़रीदाबाद 13-19 मई 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2

मोदी का 'आयुष्मान' यानी बीमा कम्पनियों की लूट का प्लान

फ़रीदाबाद (म.मो.) देश के 10 करोड़ ग़रीब परिवारों यानी 50 करोड़ आबादी को 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली योजना बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आयुष्मान भारत को। अपनी पीठ थपथपाते हुए तमाम संघी इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा बता रहे हैं। जबकि वास्तव में यह योजना झूठ के अलावा कुछ और है तो बीमा कम्पनियों की लूट कमाई को बढाने वाली कवायद।

हरियाणा में इसके लिये 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें से 120 करोड़ केन्द्र सरकार तथा शेष 80 करोड़ हरियाणा सरकार भरेगी। समझने वाली बात है कि हर साल खर्च होने वाली इस रकम से न तो कोई अस्पताल बनेगा न कोई डिस्पेंसरी; यह सारी रकम किसी बीमा कम्पनी को दी जायेगी बतौर किश्त। बीमा कम्पनी इस पैसे से उन ग़रीबों का इलाज करायेगी जिन्हें सरकारी 'सर्वे' द्वारा चिन्हित किया जायेगा। सरकार के जैसे सर्वे होते हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं और बीमा कम्पनियां किसी ग़रीब का कैसा इलाज करा कर देंगी इस से भी जनता खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है।

यह तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है कि बीमा कम्पनियां केवल लाभ कमाने के लिये होती हैं। यदि उन्हें घाटा होने लगे तो वे तुरंत कारोबार बंद करके भाग लेती हैं। कम्पनियों के इसी रुख को देखते हुए 1956 में भारत सरकार ने तमाम निजी बीमा कम्पनियों को बंद करके जीवन बीमा निगम तथा निर्जीव वस्तुओं के लिये 4 सरकारी सामान्य बीमा कम्पनियों का गठन किया था।

अब मजे की बात यह है कि मोदी सरकार 'आयुष्मान भारत' की बीमा किश्त किसी भी सरकारी कम्पनी को न देकर उन देशी-विदेशी कम्पनियों को देगी जो लूट में से कुछ हिस्सा संघियों को देंगी। सबूत के तौर पर प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के नाम पर 22000 करोड़ की किश्त 4 देशी-विदेशी कम्पनियों को दी गयी थी। इन कम्पनियों ने किसानों को बतौर मुआवजा केवल 14000 करोड़ का भुगतान करके साल भर में 8000 करोड़ का मुनाफ़ा लूटा था।

आयुष्मान भारत योजना से करीब 9 वर्ष पूर्व आर एस बी वाइ (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) का भी ऐसा ही ड्रामा कांग्रेस सरकार ने किया था। अन्तर केवल इतना था कि उसमें मरीज़ का इलाज केवल 30 000 रुपये तक का कराने का प्रावधान था जो अब 5 लाख तक का रखा गया है। उस योजना में भी सारी बीमा कम्पनियां प्राइवेट ही थीं। प्राइवेट कम्पनियों से लूट की हिस्सेदारी वसूलने में दिक्कत कोई नहीं रहती जबकि सरकारी में यह लगभग असंभव सा रहता है।

दूसरी ओर सरकार के पास ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी है। यह निगम 21000 तक मासिक वेतन पाने वाले औद्योगिक मज़दूरों, स्कूलों व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वालों से उनके वेतन का साढे 6 प्रतिशत मासिक वसूलती है। इसके बदले निगम उन्हें व उनके परिवार को तमाम तरह की चिकित्सा सुविधा व अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का दावा करता है।

हरियाणा में 30 लाख कर्मचारी इस योजना में अंशदान देते हैं। इनको चिकित्सा सेवा देने का दायित्व राज्य सरकार का है। इसके लिये राज्य सरकार ने बाकायदा एक ईएसआई हैल्थ केयर निदेशालय बना रखा है जिसमें छोटे-बड़े करीब 100 कर्मचारी काम करते हैं। राज्य के 30 लाख ईएसआई कवर्ड परिवारों के लिये अस्पताल, डिस्पेंसरियां चलाने के लिये डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ भर्ती करना, दवायें व तमाम आवश्यक उपकरण आदि खरीदने का दायित्व भी इसी निदेशालय पर है। अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की इमारत बनाने या किराये पर ले कर निदेशालय को देने का काम ईएसआई निगम का है।

अपने उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिये ईएसआई नियमावली के अनुसार बजट बनाने का काम निदेशालय का है, जो 30 लाख अंशदाताओं को देखते हुए कम से कम 800 करोड़ का बनना चाहिये परन्तु हरियाणा सरकार इसे बनाती है मात्र 125-150 करोड़ का। मजे की बात तो यह है कि 800 करोड़ के बजट में से राज्य सरकार को तो केवल 100 करोड़ ही डालना होता है शेष 700 करोड़ ईएसआई निगम डालता है।

अब समझने वाली बात यह है कि जो सरकार 100 करोड़ खर्च करके अपने 30 लाख परिवारों यानी राज्य की आधी आबादी को 800 करोड़ की चिकित्सा सुविधा सीधे दे सकती है, वह काम तो करना नहीं, हां 200 करोड़ रुपये बीमा कम्पनी को देकर चिकित्सा प्रदान करने का दावा करती है। बीमार होने पर जिस मरीज को डॉक्टर के

शेष पेज दो पर

ईएसआईसी के माध्यम से 'आयुष्मान' योजना क्यों नहीं चलाते मोदी जी ?

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) एक ऐसी सरकारी बीमा कम्पनी है जो सन् 1952 से देश भर के औद्योगिक श्रमिकों को चिकित्सा सेवा देती आ रही है। आज देश भर में करीब 4 करोड़ श्रमिक परिवार इस योजना में कवर्ड हैं।

राज्य सरकारों के सहयोग से यह बीमा निगम आज देश भर में हज़ारों डिस्पेंसरियां, सैंकड़ों अस्पताल तथा दर्जनों मेडिकल कॉलेज बना चुका है। वह बात अलग है कि धूर्त शासक वर्ग की मूर्खताओं व आपाधापी के चलते करीब आधे मेडिकल कॉलेज बन चुकने के बावजूद बंद पड़े हैं। यदि सरकार धूर्तता व मूर्खता को त्याग कर पूरी ईमानदारी से इस (ईएसआईसी) योजना को ढंग से चलाये तो उस से बेहतरीन कोई और योजना हो नहीं सकती।

लेकिन इसमें सरकार चलाने वाली भाजपा व संघ को बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें व उनके पूंजीपति मित्रों के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं। जो लूट, ठगी व मुनाफ़ाखोरी प्राइवेट बीमा कम्पनियों के माध्यम से होने वाली है, वह ईएसआईसी के माध्यम से असंभव है।

देखो रेल का खेल, मोदी सरकार कैसे हो रही फ़ेल

फ़रीदाबाद (म.मो.) मध्य दिसम्बर 2017 तक दिल्ली-पलवल-मथुरा के बीच तमाम रेलगाड़ियां जैसे-तैसे चल तो रही थीं। लेकिन इसी दौरान कोहरे के बहाने इस रूट की करीब 9 शटल एवं पैसेंजर गाड़िया रद्द कर दी गयीं। दरअसल वह एक ऐसा दौर था जब देश में लगातार एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे थे। इसी दौरान फ़रीदाबाद के आसपास कुछ गाड़ियों के पटरी से उतरने के छोटे-मोटे हादसे भी हुए। जांच करने पर पता चला था कि एक ट्रैक की 80 से अधिक फ़िश प्लेटें बहुत ढीली एवं खतरनाक स्थिति में थीं।

इन हालात में मोदी के रेल मंत्रालय ने महीनों तक यहां से 'कोहरा' हटने ही नहीं दिया और इसी बहाने उक्त रेलें बंद रखी गयीं। फ़िर सिग्नल प्रणाली, तो कभी लॉकिंग व अन लॉकिंग के नाम पर तो कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफ़ार्म पर मरम्मत के काम को बहाना बना कर उक्त ट्रेनों को बन्द रखा गया।

30 से 40 हज़ार दैनिक यात्रियों के दबाव में रेलवे आये दिन 'कल' से सेवा बहाल करने का वायदा करके अपनी जान छुड़ाता रहा, लेकिन वह 'कल' कभी आता नहीं था। हां बीच-बीच में कभी कोई तो कभी कोई ट्रेन चला दी जाती। जब महिलाओं का दबाव बढता तो महिला स्पेशल चला दी जाती। जब अन्य यात्रियों का दबाव बढता तो महिला स्पेशल की जगह दूसरा शटल चला दिया जाता। खबर लिखे जाने तक भी कम से कम 4 ट्रेनें इस रूट की बंद पड़ी हैं।

रेलवे देश का सबसे बड़ा मुनाफ़ा देने की क्षमता वाला उद्योग है। यह मुनाफ़ा नकद ही नहीं बल्कि यात्रा से महीनों पहले भुगतान वसूलने वाला उद्योग है। इसके बावजूद न तो सरकार से सभी गाड़ियां चलाई जा रही हैं और जो 13000 गाड़ियां देश भर में चल भी रही हैं, उनमें से राजधानी व शताब्दी गाड़ियों को छोड़ कर लगभग सभी ट्रेने देरी से चल रही हैं। देरी भी मिंटों या घन्टों की नहीं दो-दो तीन-तीन दिन की देरी से चल रही हैं। हां, जो गाड़ी 48 घंटे या 72 घंटे की देरी से चलेगी उसे 2 या 3 दिन की देरी से चलना ही कहा जायेगा।

ट्रेनें चलें भी तो कैसे चलें ? रेलवे में 2 लाख से अधिक पद कई बरसों से रिक्त पड़े हैं और प्रति माह 2-3 हजार पद खाली होते रहते हैं। सरकार की मूर्खता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिक्त पद केवल इस लिये नहीं भरे जा रहे कि इससे सरकार को वह पैसा बच रहा है जो उसे उनके वेतन आदि पर खर्च करना पड़ता। जाहिर है कर्मचारियों की इतनी भारी कमी के चलते न तो ट्रैक की नियमित देखभाल हो पा रही हैऔर न ही आवश्यक मरम्मत आदि का काम। ड्राइवर व अन्य लोको स्टाफ़ जो रात दिन चलता ही रहता है उसे भी जब क्षमता से अधिक काम करना पड़ेगा तो यही दुर्दशा होगी जो रेलवे की हो रही है।

रही-सही कसर पूरी करने के लिये एक से बढ़ कर एक भ्रष्टाचारी रेलवे में घोटाले करने में जुटा है। इसका बेहतरीन उदाहरण मनमोहन सरकार के दौरान उस वक्त देखने को मिला था जब चंडीगढ़ से सांसद बने पवन बंसल रेल मंत्री थे। उस वक्त रेलवे बोर्ड का मेम्बर टेक्नीकल बनने के लिये एक रेलवे अफ़सर ने एक करोड़ की रकम बतौर रिश्वत मंत्री पवन बंसल के भांजे के मार्फ़त भिजवाई थी। इसी से समझा जा सकता है कि रेलवे में खरीदारी में कितना बड़ा घोटाला हो सकता है।

रेलवे में पहले डिविजन स्तर पर ही आवश्यक साजो-सामान की खरीदारी आवश्यकतानुसार तुरंत कर ली जाती थी। परन्तु रेलवे बोर्ड में बैठे उच्चाधिकारियों को इस प्रक्रिया में बराबर कमीशन नहीं मिलता था। सारा कमीशन खुद हड़पने के लिये बोर्ड में बैठे उच्चाधिकारियों ने पूरे देश भर की खरीदारी करनी खुद शुरू कर दी। इससे न तो समय पर सामान खरीदा जा सकता है और न ही समय पर यथास्थान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में फ़िर हादसे तो होंगे ही।

पाठकों ने पिछले दिनों जंतर-मंतर पर रेलवे अपरेंटिसों का धरना व आन्दोलन के बारे में तो जरुर देखा सुना होगा। पॉलिटेक्निक व आईटीआई से पढने के बाद रेलवे कड़ी परीक्षा के आधार पर अपरेंटिस भर्ती करके उन्हें काम सिखाती है। 2-3 वर्ष पश्चात जब वे पूर्ण ट्रेंड हो जाते हैं तो उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में भर्ती करती रही है। परन्तु गत 4 वर्षों से सरकार ने इनकी भर्ती पर आंशिक रोक लगा दी है। इन ट्रेंड लोगों में से 80 प्रतिशत अपनी मर्जी से यानी संघ की सिफ़ारिश पर भर्ती किये जाने का प्रावधान बना दिया। लेकिन वास्तविक भर्ती किसी की भी नहीं हुई। अब पिछले दिनों 90000 पदों की भर्ती निकाली गयी है जिसकी प्रक्रिया में ही 2-4 साल लगने तय हैं, तब तक खाली पदों की संख्या 4 लाख तक पहुंचना तय है।

ऐसे में रेलवे को भारी मुनाफ़े की जगह भारी घाटा होना तो निश्चित है ही, साथ में रेल से यात्रा करने वालों की मुसिबतें व जोखिम का बढना भी स्वाभाविक है।

नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भगा देने के बाद मोदी गिरोह का झूठ पकड़ा गया

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

सरकार ने बहुत हल्ला मचाया था कि हमने तो उन दोनों की लगभग 8 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया,जब पुणे के आरटीआई ऐक्टिविस्ट विहार ध्रुवे ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों का ब्योरा मांगा जिसे देने से ईडी ने इनकार कर दिया।

आरटीआई ऐक्टिविस्ट विहार ध्रुवे ने नीरव और मेहुल की कंपनियों को जारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उनके द्वारा ली गई राशि , नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने के लिए अधिकारियों के यात्रा खर्च, भारत व विदेश में वकीलों को सलाह के लिए दी गई फीस आदि से संबंधित जानकारी भी मांगी थी।

ईडी ने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 के तहत अपवाद का संदर्भ दिया है। हालांकि यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस धारा के तहत यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में जानकारी को कोई केंद्रीय एजेंसी रोक नहीं सकती जबकि यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का ही मामला है।

लेकिन बात सिर्फ एक इसी आरटीआई की नही है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार में आरटीआई के 2 लाख मामले लंबित हैं। इस सरकार ने आरटीआई कानून की धज्जियाँ बिखेर दी हैं।